लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16- 31 मई, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 66

"जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते।"

: अज्ञात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म दिन पर विशेष

3

प्राकृतिक खेती का फायदा ले रहे रेवाड़ी के किसान

6

सार्वकालिक मार्गदर्शक श्रीमद्भगवद्गीता

8

नई आबकारी नीति से बढ़ेगा राजस्व

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमे कई अहम निर्णय लिये गए। मुख्यमंत्री के मुताबिक लिए गए अहम निर्णय प्रदेश के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

बैठक में जिस नई आबकारी नीति- 2023-24 को अनुमोदित किया गया है, वह उन संसाधनों को उत्पन्न करने की सुविधा भी देती है, जिनका उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार ने नई नीति के सफल कार्यान्वयन के साथ 10,000 करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार करने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करना है। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के लक्षित संग्रह के साथ खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए किया जाएगा।

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटी (क्राफ्ट) ब्रेवरीज की लाइसेंस फीस कम की गई है तथा वाइनरी को बढ़ावा देने के लिए सुपरवाइजरी फीस में कमी की गई है। नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 'मशः 2023-24 में 2500 से 2400 कर दिया गया है। नई नीति में देशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयातित विदेशी शराब के मूल कोटे में बढ़ोतरी की गई है।

पंचकूला में श्रीमाता मनसा देवी मंदिर के आस-पास अधिसूचित पवित्र क्षेत्रों तथा जिन गांवों में गुरुकुल चल रहे हैं, वहां शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे।

निकाय चुनाव में बीसी- ए को आरक्षण

शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति मिल गई है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने इस विषय पर आकलन करने के लिए गहन जांच की गई थी। आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए को शहरी स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद नागरिकों के ब्लॉक-ए के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो सकती है। नगर निकायों में महापौर व अध्यक्ष के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिए आरक्षित होगा। दशमलव मान 0.5 या अधिक होने की स्थिति में इसे अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक बनाया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ग से प्रदेश में आठ चेयरमैन व 300 पार्षद चुने जाएंगे।

ओल्ड पेंशन स्कीम

प्रदेश में 2005 से पूर्व के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई । ओपीएस का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी होने से पहली हुई थी। जानकारी के मुताबिक 28 अक्तूबर 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति से पूर्व के कर्मचारियों को यह लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में जारी निर्देशों के मुताबिक वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है।

स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए नए स्वास्थ्य केंद्र

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार ने इस कड़ी में कुछ बड़े अस्पतालों के अलावा छह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 25 उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किये हैं। मंत्रीमंडल की बैठक में स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी चिकित्सा संस्थानों को जनता को समर्पित किया।

भिवानी जिले के आंची देवी मेघराज जिंदल सिविल अस्पताल, सिवानी और करनाल में 50 बिस्तरों वाले अस्पतालों के अलावा फतेहाबाद, रोहतक, कैथल, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा, पंचकूला, चरखी दादरी, जींद, यमुनानगर, हिसार, गुरुग्राम, नारनौल और कुरुक्षेत्र में 25 उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (यूएचसी) तथा 4 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर शामिल हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी मरीजों को किफायती दरों पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलें। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष के लिए 9647 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- **छह नए उपमंडल मानेसर (गुरुग्राम), नीलोखेड़ी (करनाल), इसराना (पानीपत), छछरौली (यमुनानगर), नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़), और जुलाना (जींद) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।**
- हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम के तहत अधिकतम मासिक अंशदान अब अंशदायी के मूल वेतन तक तो होगा परन्तु एक वित्तीय वर्ष में मासिक अंशदान की राशि उस वित्तीय वर्ष में जमा किये गए बकाया अंशदान की राशि सहित पांच लाख रुपए की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।
- विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप-सी) फील्ड कार्यालय सेवा नियम में बेहतर योग्यता और वेतनमान पाने वाले ग्राम सचिव-2 और महाग्राम सचिव के नए पदों के सृजन के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- माइनिंग गार्ड के 22 पदों को सीनियर माइनिंग गार्ड में अपग्रेड करने के बाद हरियाणा खान एवं भू विज्ञान विभाग फील्ड (ग्रुप सी) सर्विस रूल्स, 1998 में सीनियर माइनिंग गार्ड के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिए योग्यता/मानदंडों में संशोधन किया गया है।
- उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक/कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति में संशोधन के संबंध में स्वीकृति।
- शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक भूखंडों और एससीओ में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी। अधिनियम की धारा 3-सी एक कॉलोनी में स्थायी रूप से हस्तांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के उद्देश्य से स्वतंत्र आवासीय मंजिलों के पंजीकरण को सक्षम बनाती है।
- सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नामक एक नया विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया।
- कृषि-व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति को अधिसूचित करने का उद्देश्य वर्ष 2023 तक 3,500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में 20,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन करना और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं (फल, सब्जियां), डेयरी, मत्स्य पालन आदि में प्रसंस्करण के स्तर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना रहेगा।
- गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति।

चिरंजीवी भवः

समाज कल्याण को समर्पित रहा मुख्यमंत्री का जन्मदिवस

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिवस कई मायनों में विशेष रहा। सीएम आवास 'संत कबीर कुटीर' पर संत महात्माओं की उपस्थिति में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया तथा जन कल्याण की नीतियों को और अधिक सुदृढ़ता से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। संत महात्माओं ने मुख्यमंत्री को न केवल चिरंजीवी भवः का आशीर्वाद दिया बल्कि समाज कल्याण की दिशा में चलाए जा रहे अभियानों में विशेष सहयोग देने का भी भरोसा दिया।

इस मौके पर जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान विषय पर विशेष चर्चा की गई। संत महात्माओं ने राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की और सफलता की कामना की। अलवर के सांसद महंत बालक नाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज व अन्य संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि संत महापुरुषों ने सदैव सामाजिक बुराइयों के खिलाफ़ जन-जन को जागरूक करने का काम किया है। महापुरुषों के विचारों और उनके आह्वानों का अनुसरण करते हुए आम जनमानस ने भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हाथ से हाथ मिलाने का संकल्प लिया है।

इसलिए संत महापुरुषों की ओर से जल संरक्षण और नशा मुक्ति अभियान में सहयोग करने से निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी।

सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार नशा तस्करों पर सख़्त कार्रवाई कर रही है। इसके लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है तथा जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सैल्स बनाए हैं जो बखूबी कार्य कर रहे हैं।

नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री को रोकने हेतु मोबाइल ऐप 'साथी' बनाया है। आपराधिक गतिविधियों के डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर हॉक विकसित किया है तथा पंचकूला में अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह ने जल संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर विभिन्न विभागों में अस्थाई नौकरी के लिए 896 आवेदकों को जॉब ऑफर भेजे। इनमें से 632 युवाओं को तुरंत प्रभाव से परिनियोजन पत्र जारी किए। एचकेआरएनएल के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। भेजे गए जॉब ऑफर में 136 फायरमैन/ड्राइवर, 117 एनालिस्ट एसोसिएट, 106 आयुष योग सहायक, 86 ईआरवी ड्राईवर, 64 लेबोरेट्री सुपरवाइजर, 41 आर्ट एजुकेशन सहायक इत्यादि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों को तोहफ़ा देते हुए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' की शुरुआत की। उन्होंने अयोध्या यात्रा के लिए पंचकूला से बस को झंडी दिखाकर रवाना किया।

संपादकीय

निरंतर जारी है विकास का क्रम

विकास के मार्ग पर आगे बढ़े बिना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक भी दिन ऊर्जा के साथ बीत नहीं पाता। पिछले साढे आठ वर्षों में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक विकासात्मक तथा जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। परिवार-पहचान-पत्र अनियमितताओं व गड़बडियों को पकडने में अहम दस्तावेज साबित हुआ। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किए गए सर्वे के आधार पर प्रदेश में 12 लाख 50 हजार नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार के एक लाख 20 हजार रुपए की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपए करने के फलस्वरूप प्रदेश में आयुष्मान कार्ड एवं चिरायु हरियाणा योजना के तहत सात लाख लोगों ने मुफ्त में अपना इलाज करवाया है, जिस पर 950 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। उन्होंने बताया है कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है जिसके सं य सदस्यों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी कहीं अधिक है।

यह भी स्पष्ट है कि 'आयुष्मान कार्ड' से प्रदेश में सात लाख विपन्न लोगों ने निःशुल्क इलाज कराया है। यह अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है।

विगत कुछ सप्ताहों से मुख्यमंत्री निरंतर जनसंवादों के माध्यम से ग्रामीण आंचल के लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं और उनकी दैनिक जीवन की समस्याओं का वहीं से समाधान करने का प्रयास हो रहा है ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के लिए सचिवालय तक न आना पड़े। इन जनसंवादों के द्वारा प्रशासन व लोकधारा के मध्य दूरी समाप्त हो रही है और मुख्यमंत्री, मुख्यसेवक की भूमिका सार्थक ढंग से निभा पा रहे हैं।

- सलाहकार सम्पादक

सुपर-100 बैच का रहा बेहतर परिणाम

शैक्षणिक प्रतिभाओं को और अधिक निखारने के लिए शुरू किया गया सुपर-100 कार्य म काफी सफल हो रहा है। बैच 2021-23 से कुल 89 विद्यार्थी जेईई मेन्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर जेई एडवांस के लिये क्वालीफाई हुए हैं। प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों में 99 प्रतिशत से ऊपर के अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हरियाणा के है। सिरसा से विकास की कुल 99.58 प्रतिशत उपलब्धि रही, जिसमे गणित की 99.79 प्रतिशत तथा भौतिक विज्ञान की 98.47 प्रतिशत और रसायन विज्ञान में 97.57 प्रतिशत से विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

सुपर-कार्य म में शीर्ष 5 छात्रों का प्रदर्शन बहुत ही शानदान रहा है। सिरसा के विकास 99.58 प्रतिशत, हिसार के विकास कुमार 99.00 प्रतिशत, रोहतक के आदित्य मोहन 97.98 प्रतिशत, जीन्द के अजय कुमार 97.81 प्रतिशत और जीन्द के आकाश 97.22 प्रतिशत अंक लेकर अति उत्तम प्रदर्शन रहा है।

छात्राएं भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, जींद जिले से महक ने 96.55 प्रतिशत और नेहा ने 95.64 प्रतिशत अंक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण की है।

गौरतलब है कि कार्यक्रम से निकले सैकड़ों विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंच चुके हैं। इस प्रकार यह कार्य म बहुत ही सफल एवं कारगर साबित हो रहा है।

शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि सुपर-100 कार्य म हरियाणा सरकार एवं विकल्प फाउंडेशन द्वारा शुरू की गयी एक अद्वितीय पहल है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धा का माहौल प्रदान करना है। यह एक आवासीय कार्य म है जो विद्यार्थियों को आईआईटी और एनईईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एक विशेष चयन प्र िया के माध्यम से दो वर्षीय प्रशिक्षण कार्य म का भाग बनाया जाता है जिसमें प्रशिक्षण का कार्य विकल्प फाउंडेशन तथा अन्य सभी खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

मन की बात

मन से होकर अंतर्मन तक
गूंजे सब सच्चा संवाद
जुड़ जाता है देश ये सारा
जब जब होती मन की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' के अंतर्गत स्वच्छ भारत, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, परीक्षा पे चर्चा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ भारत, योग, गीत, संगीत, किताब के प्रति प्रेम, स्थानीय कलाओं और देसज कारीगरों को पहचान और ब्रांड की कीमत सहित अनेक विषयों पर चर्चा कर समाज को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया। इससे इन क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले सामान्य लोगों को निसंदेह नई पहचान मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से देश के नौजवानों में देश भक्ति की एक नई लहर उत्पन्न करने का काम किया तथा उन्हें नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल, गुरू गोविंद सिंह, भगवान बिरसा मुंडा जैसे शहीदों के प्रति जानने और सम्मान प्रकट करने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना', 'वोकल फार लोकल', 21वीं सदी की 'तकनीकी दक्षता', 'प्रतिभा परिश्रम' तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति युवाओं को जागृत किया। उन्होंने बताया कि समाज में परिवर्तन का कार्य वैज्ञानिक, तर्कशील व भारतीय मूल्यों पर आधारित संस्कारवान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सुनील जागलान और प्रदीप सांगवान से बात की। गांव बीबीपुर के सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर अभियान से जुड़े हैं जिनके प्रयासों से बेटियों को लेकर समाज में सकारात्मक असर पड़ा तथा इससे लड़कियों को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने अपने एपिसोड में इसका जिक्र किया। जल्द ही 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान वैश्विक हो गया। इस अभियान का मकसद लोगों को जीवन में बेटी के महत्व को समझाना था। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अनेक प्रयासों के परिणाम से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान पहाड़ों के स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। प्रदीप सांगवान व उनकी टीम 'हीलिंग हिमालय' अभियान के माध्यम से हिमालय के अलग-अलग इलाकों में फेंके गए कचरे की सफाई करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान के कारण अब पर्वतारोही भी स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट कर रहे हैं।

प्रदीप सांगवान ने प्रधानमंत्री को बताया कि वर्ष 2020 के बाद जब 'मन की बात' में उनके अभियान का जिक्र हुआ उसके बाद बहुत बदलाव आया। पहले वे साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे लेकिन आज वे अलग-अलग स्थानों से प्रतिदिन पाँच टन कचरा इकट्ठा करते हैं। अब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता बढ़ी है, लोग खुद आगे आकर इस अभियान से जुड़ रहे हैं।

हरियाणा के लिए विशेष रहा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य म के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है तथा लोगों को नई दिशा दी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्य म में हरियाणा में की गई नई पहलों का कई बार जि किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के युवकों द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने और शहरों में भी नवयुवकों द्वारा इसी प्रकार प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाने, बाढ़सा में एम्स में एक संस्था द्वारा बनाई गई सराय इत्यादि के बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्य म में उल्लेख किया है। इससे पहले भी कई एपिसोड में प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों और प्रगतिशील किसानों की तारीफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार ने जन जागृति के लिए कई कदम उठाए हैं।

कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 स्थानों पर सामूहिक कार्य म का आयोजन किया गया था। समस्त प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना।

समाज सेवियों को मिली नई पहचानः राज्यपाल

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्य म से देश के दूर दराज क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले अनेकों कर्मठ समाज सेवियों को नई पहचान मिली है। श्री दत्तात्रेय राजभवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्य म के 100वें एपिसोड के पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में हरियाणा के नौ प्रतिभागियों सुनील जागलान, रजनी, प्रशांत सिंह कन्हैया, संदीप कुमार, वीरेंद्र यादव, लछमन दास, सुभाष कांबोज, प्रदीप सांगवान, तनु मलिक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की।- संवाद ब्यूरो

हरियाणा में 22 प्रतिशत बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

हरियाणा लगातार जीएसटी कलेक्शन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2022 में राज्य का जीएसटी कलेक्शन जहां 8,197 करोड़ था, वहीं वर्ष 2023 में यह बढ़कर 10,035 करोड़ हो गया है। जीएसटी कलेक्शन के संबंध में हरियाणा की तुलना अगर पड़ोसी राज्यों से करें तो पंजाब में 16 प्रतिशत, हिमाचल में 17 प्रतिशत, दिल्ली में 8 प्रतिशत और राजस्थान में 5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। ऐसे में देखा जाए तो हरियाणा की ग्रोथ रेट इन राज्यों से कहीं अधिक है।

देश में 'एक देश-एक कर' की अवधारणा पर लागू जीएसटी प्रणाली बेहद कारगर है। जीएसटी की प्र िया सरल होने से न केवल उद्यमियों को फायदा पहुंचा है, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है जिसे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। गौरतलब है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की तर्ज़ पर अब नगर निकायों में भी बीसी (ए) वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की रावगढ़ के सरंपच को ई-टेंडरिंग का ब्रांड अम्बेसडर बनाने की घोषणा की। सरपंच ने नई व्यवस्था से ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरपंचों की बदनामी भी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्म दिन पर विशेष

शासन के महाप्रबंधक

खुद रहे अटल, व्यवस्था डाली बदल

मनोज प्रभाकर

भौतिकी, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान की पढ़ाई करने वाले युवा मन्नू ने सपना बुना था कि वह बड़ा होकर डाक्टर बनेगा और समाज की खूब सेवा करेगा। मगर परिवार की माली हालत के चलते वह डाक्टर न बन सका। सेवा की सनक मन में रही। देश व समाज सेवा की खातिर वह हर पारिवारिक सुख को हाशिए पर रखता चला गया। घर परिवार वाले नाराज हुए तो होने दिया, कोई परवाह नहीं की। चरैवति चरैवति की धुन के साथ आगे बढ़ता रहा।

परिवार की गुजर-बसर के लिए खेती की, सब्जी बेची व थोड़ा बहुत कपड़े का कारोबार किया। जीवन की हर परिस्थिति का सामना किया मगर सेवा की लौ को मध्यम नहीं होने दिया। उम्र के 62वें पड़ाव पर संघर्ष का परिणाम आया। परिणाम के मुताबिक मन्नू से बना मनोहर लाल पहले विधायक बना और फिर शासन व्यवस्था का डॉक्टर यानी मुख्यमंत्री बन गया। हरियाणे का मुख्यमंत्री।

यशस्वी एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री मनोहर लाल विगत करीब नौ वर्ष से बिना रुके, बिना थके प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। लोगों का जीवन सहज व सरल कैसे हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्य में अपनी राजनीतिक दक्षता का भरपूर इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था का 'उपचार' कर रहे हैं। परिस्थिति के मुताबिक 'शल्य चिकित्सा' की जरूरत पड़ती है तो वह भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि उनके लिए पूरा प्रदेश एक है, एक परिवार है। बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का चहुंमुखी विकास उनका लक्ष्य है। कोई परिवार अभाव में न जीए, यह उनका संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जीवन की जटिलताओं को करीब से देखा है, इसलिए वे सबको स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। इस अभियान में 'पारदर्शिता' उनकी संवाहक बनी है। सही को सही व गलत को गलत कहने की ताकत यहीं से मिल रही है।

मनोहर लाल ने जब पहली बार 'कुर्सी' संभाली थी तो प्रदेश में व्यवस्था को लेकर निराशा का माहौल था। अमीर, अमीर होता जा रहा था और गरीब, गरीब। हर क्षेत्र में भेदभाव व अन्याय का बोलबाला था। शिकायत करें, तो कोई सुनने वाला नहीं था।

मुख्यमंत्री बनते ही मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार ईमानदार सरकार के सिद्धांत पर चलेगी। इसमें कोई किंतु-परंतु वाली बात नहीं होगी। करीब नौ साल बाद का परिणाम यह है कि आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। भेदभाव का कहीं कोई नाम नहीं है। अपने काम करवाने के लिए लोगों को जन प्रतिनिधियों के पीछे-पीछे नहीं भागना पड़ता। भागमभाग की अव्यवस्था बीत चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संकल्प से नहीं डिगे, अटल रहे। व्यवस्था बदलने का काम किया जा रहा है।

परिवार पहचान पत्र के जरिए तमाम योजनाओं को जोड़ा गया है ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। पीपीपी मॉडल न केवल गरीब व्यक्ति को विभिन्न सेवाओं की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाएगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ने 9 लाख परिवारों को 279 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर उन्हें नई उड़ान देने का काम किया है। मुख्यमंत्री की ईमानदार कार्यशैली ने आम लोगों को बिजली के बिल भरने के लिए प्रेरित किया है। जिसके चलते लाइन-लॉस कम हुआ है। आज प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश के अनुकूल माहौल की वजह से बीते दिनों में बड़े स्तर पर छोटे, मंझले व बड़े उद्योग लगे हैं जिनमें लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। सक्षम युवा योजना से 1.71 लाख युवाओं को 100 घंटे का रोजगार मिला है। योजना के माध्यम से 92 हजार युवाओं को उबर, ओला जैसी कंपनियों में काम मिला। इतना ही नहीं राज्य सरकार अब प्रदेश के युवा के लिए विदेशों में भी रोजगार तलाश रही है।

आठ साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्तमान सरकार ने अक्टूबर 2014 के 105 कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 173 की। इसी तरह महिला कॉलेज 29 से बढ़ाकर 60, मिडल स्कूल 2397 से बढ़ाकर 5912, आईटीआई 142 से 181, राजकीय संस्कृति स्कूल 13 से बढाकर 138 किए हैं। हाल ही में 250 स्कूलों में पीएम श्री योजना शुरू होना ऐतिहासिक कदम होगा।

हरियाणा, देश का पहला प्रदेश है जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। किसानों को फसल भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाता है। बीते तीन सीजन में 56,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया गया।

किसानों को पहली बार किसी सरकार ने फसल खराब पर 9414 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। इजराइल की तर्ज पर प्रदेश में आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए डायल-112 योजना कारगर साबित हुई है। मात्र एक साल में 9,20,563 कॉल का समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक स्तर पर महिला थाना, स्कूल-कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध पर फांसी की सजा और 'दुर्गा शक्ति' जैसे अभियान चलाकर राजनीति में सामाजिक दायित्व का नया अध्याय जोड़ा है।

मनोहर लाल की साफ नीयत व नीति का ही परिणाम है कि आज प्रेदश के खेल-खिलाड़ी राज्य का सिर ऊंचा कर रहे हैं। खेल तालिका में हरियाणा देश भर के 30 फीसद पदक जीतता है। राज्य में 1100 खेल नर्सरियां खोली गई हैं। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2023-24 में 526 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की पैरवी ने देश की अन्य सरकारों को सोचने पर मजबूर किया है। प्रदेश के 43 विभागों के 214 कॉडर में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई गई है। अब किसी भी कर्मचारी को कम्प्यूटर के एक क्लिक से मनपसंदीदा स्टेशन मिल जाता है। ई-पीडीएस सिस्टम होने से लोगों को अंगूठा लगाकर राशन मिल रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांशी स्वामित्व योजना की चर्चा सर्वत्र है, जिससे अंग्रेजों के काल से जारी लाल डोरा सिस्टम खत्म हुआ। इससे हर गरीब को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा तो जमीनी झगड़े सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे।

'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' के मूल मन्त्र के साथ सरकार समान विकास की राह पर अग्रसर है। वह दिन दूर नहीं, जब हर जिले से कोई न कोई राजमार्ग गुजरेगा। गरीब व जरूरतमंद परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, मनोहर सरकार की प्राथमिकता में है। अक्टूबर 2014 में जहां प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 13 हो गई है। एमबीबीएस सीटों में अढ़ाई गुणा बढ़ोतरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का सफल क्रियान्वयन मनोहर लाल की विशेष उपलब्धि है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं। ऑक्सी-वन, प्राण वायु देवता पेंशन, मेरा पानी-मेरी विरासत जैसी योजनाओं की चर्चा सर्वत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक रूप से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुले मन से प्रशंसा कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री तीर्थ योजना

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन्म दिन पर करीब 200 बुजूर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। रोडवेज की बस पंचकूला से अंबाला कैंट तक पहुंचेगी और अंबाला से रेल के माध्यम से ये यात्री अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। इन यात्रियों का आने जाने का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। मनोहर लाल ने कहा कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ योजना' की शुरुआत पंचकूला से की जा रही है। इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य भव्य तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर वर्ष 2024 में श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे।

दिव्यांग महिला को आर्थिक सहयोग

मानवता की सेवा को समर्पित मुख्यमंत्री मनोहर लाल समूचे प्रदेश को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री हैं। वे सच में हर किसी का दुख हरने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ से पंचकूला की ओर जा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे एक दिव्यांग महिला को देखा। उन्होंने अपना काफ़िला रुकवाकर उस महिला की परेशानी जानी। मुख्यमंत्री ने महिला को मौके पर ही अपनी तरफ़ से आर्थिक सहयोग दिया और सरकारी योजनाओं का लाभ देने का भरोसा दिलाया।

महिला ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बारे में जैसा सुना था वे वैसे ही हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सदैव स्वस्थ रहे और उनकी आयु लंबी हो।

शिशु गृह के बच्चों संग मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना जन्मदिन पंचकूला के सेक्टर-15 स्थित शिशु गृह में भी सादगी से मनाया। स्कूली बच्चों ने 'भारत माता की जय' नारों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

मनोहर लाल ने बच्चों के लिए सुविधाओं व विभिन्न गतिविधियों के बारे जानकारी ली। कक्षा छठी से दसवीं तक के बच्चों के लिए चलाए जा रहे वर्चुअल क्लासरूम के बारे में भी जानकारी ली। वर्तमान में 50 बच्चे वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे हैं। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने मुख्यमंत्री को उनकी माता का चित्र भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार भेंट किए।

राज्य सरकार ने राज्य की 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा पोर्टल पर लाइव कर दिया है। शहरों के निवासी अपनी -अपनी प्रॉपर्टी की जाँच कर सकते हैं। किसी भी शिकायत के समाधान हेतु पालिका में ' हेल्प डेस्क' पर संपर्क कर सकते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार तथा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों से 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।

जन संवाद

मनोज प्रभाकर

सरकार की नीतियों व योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर किस स्वरूप में तथा किस गति से पहुंच रहा है, की जानकारी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू किया है। प्रदेश की जनता भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है। मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच बैठकर न केवल उनका हाल चाल जान रहे हैं बल्कि उनकी मांगों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश का कोई भी व्यक्ति या परिवार परेशानी में न रहे,अभाव में न जीए। शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी परिवार के पास पर्याप्त आय का साधन नहीं हैं तो उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए संबंधित विभाग के मार्गदर्शन में बैंक संस्थाओं की ओर से उचित सहयोग दिलाया जा रहा है।

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी नीतियां चलाई गई हैं। जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए उनका फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिना किसी क्षेत्रवाद या बिना किसी जातिवाद के हर किसी को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की ओर से जो मांगें मानने की होती हैं उन पर तुरंत विचार किया जा रहा है तथा जो न मानने की हैं उनका भी मौके पर ही जवाब दिया जा रहा है। आम लोगों में मुख्यमंत्री के इस स्पष्टवादी रवैये की खूब तारीफ हो रही है। लोग कहते हैं, 'यो मुख्यमंत्री खड़तल सै, औरां की तरियां कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ण वाली बात कोन्या करता।'

मनोहर लाल कहते भी हैं कि ईमानदारी से सरकार चलाना और विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। लोगों का जीवन ज्यादा से ज्यादा सरल बने और लोगों को कहीं लाइनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए गए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर विकास कार्य करवा रही हैं, जो निरंतर जारी रहेंगे।

मनोहर लाल ने कहा कि आज किसानों को फसलों की खरीद व अन्य सब्सिडी के पैसे सीधे उनके खातों में भेजे जा रहे हैं। किसानों को अब बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यही कारण है कि लोग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धान की फसल छोड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया है और इसके लिए जो किसान अपने खेत में धान की फसल नहीं लगाता है उसे 7 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।

सरपंच सबको साथ लेकर करें विकास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी ग्राम पंचायतों से अपील की है कि वे गांव के विकास पर पूरा ध्यान दें, विदित रहे पारदर्शिता उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कोई भी काम करें तो सभी पंचों व गांव के अन्य प्रबुद्धजनों को साथ लेकर करें। इस तरह से किये गए कार्यों पर कोई उंगली उठने की गुंजाइश नहीं रहती। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी परेशान करता है तो उसकी जानकारी उच्चाधिकारी को दें। उन्होंने सभी सरपंचों से कहा कि वे 3 महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक अवश्य करें। ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित करके भेजे जाएंगे, उन विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करवाया जाएगा।

बारना की महिलाओं ने लिखी रोजगार की नई इबारत

कुरुक्षेत्र के गांव बारना ने स्वयं सहायता समूहों के द्वारा रोजगार के अनेक अवसर सृजित कर स्व रोजगार की एक नई इबारत लिखी है। वर्तमान में गांव में इस समय करीब 30 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। यही नहीं करीब 20 स्वयं सहायता समूह के पास लगभग 20 लाख रुपए बचत राशि के रूप में बैंक खातों में पड़े हैं। गत 10 मार्च को करनाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योति महिला स्वयं सहायता समूह को 50 हजार रुपए का चेक देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान बारना गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन द्वारा चलाये जा रहे समूहों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के अपने परिवारों के पालन-पोषण करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर देने के प्रयासों की सराहना की।

बारना गांव की स्वयं सहायता समूह चलाने वाली सुमन बताती हैं कि गांव में स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने आर्थिक जीवन को भी बेहतर बना रहे हैं। आज के इस दौर में स्वयं सहायता समूह सामुदायिकता और सामाजिकता की भावना को संजो कर रखे हैं। स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं।

प्रोत्साहन राशि

सुमन बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह के किसी एक सदस्य को नेतृत्व दे दिया जाता है, जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन-देन में आसानी होती है। प्रदेश सरकार भी इन स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इनकी सहायता के लिए प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के गठन पर 20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर एक भैंस के माध्यम से दूध बेचने का काम किया था, जिससे उनको काफी मुनाफा हुआ। इसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही उन्होंने अपने पति के लिए माल ढोने वाली गाड़ी भी ली है। उन्होंने बताया कि गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों ने गांव में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कपड़े की दुकान, दूध की डेयरी, बिस्तर, बर्तन की दुकान, खल की दुकान इत्यादि का काम किया है। सभी महिलाएं इकट्ठे होकर अपनी बचत का पैसे डालती हैं।

गांव के विकास कार्यों के लिए बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बारना गांव में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 56 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, जिससे गांव में रास्ते, विभिन्न चौपाल, अंबेडकर भवन के निर्माण सहित अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। गांव बारना में 125 सरकारी नौकरियां लगी हैं, जिनमे 52 केंद्र व प्रदेश सरकार की और 73 नौकरियां कौशल रोजगार निगम की ओर से लगी हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला में गत समय में लगाए गए तीन अंत्योदय उत्थान मेलों में ऐसे परिवार जिनकी आय सालाना 1 लाख 80 हजार रुपये से कम थी, उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2500 से अधिक लोगों को ऋण प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बारना गांव में 3382 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 678 लोगों ने लाभ लिया है। इसके लिए सरकार की ओर से 94 लाख 73 हजार रुपए अस्पतालों को प्रदान किए गए हैं।

जनसंवाद कार्य' म में मुख्यमंत्री ने आसपास के गांवों के करीब 6 सरपंचों से भी बातचीत की और उनकी सीवरेज, स्वास्थ्य, बसों की समस्या, जल निकासी, पानी, तालाब, लड़कियों के स्कूल इत्यादि से संबंधित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

हरियाणा पुलिस द्वारा एक अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक ''आपरेशन स्माईल'' चलाया गया जिसके तहत 722 बाल श्रमिक और 405 भिक्षुओं का रेसक्यू किया गया।

एम्स, रेवाड़ी की स्थापना के लिए 208 एकड़ भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। भिवानी में पंडित नेकी राम शर्मा, राजकीय मेडिकल कॉलेज 535.55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।

जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल पर जन संवाद कार्यक्रम के तहत आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को अपलोड कर पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ता के पास समस्या बारे संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 600 से अधिक सेवाएं आती हैं। इनके अलावा आने वाली सभी समस्याओं को अधिकारी समयबद्ध ढंग से निदान सुनिश्चित करेंगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवाद करते समय सरकार के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला एवं मुख्यालय स्तर पर इन समस्याओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों समस्याओं का निदान के लिए शहरी स्तर पर नगर दर्शन पोर्टल एवं गांव स्तर पर ग्राम दर्शन पोर्टल बनाए गए है। इन पर नागरिक घर बैठे ही अपनी समस्याओं एवं विकास कार्य करवाने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वह शिकायत अधिकारी के पास स्वतः ही चली जाएगी और वे उन पर संज्ञान लेकर एस्टीमेट एवं बजट आदि का प्रावधान कर पूरा करने का कार्य करेंगे।

बीपीएल राशनकार्ड धारकों को नहीं लगेगा 'बिजली का करंट'

बीपीएल राशन कार्ड की अर्हता के लिए बिजली बिल की लिमिट 9000 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दी गई है। अर्थात साल भर में बिजली का बिल अगर 12 हजार रुपए तक भी होगा तो बिल की वजह से उस परिवार का नाम बीपीएल श्रेणी से काटा नहीं जाएगा।

अभी तक यह अर्हता नौ हजार रुपए थी, जिसके चलते हजारों परिवारों के नाम बीपीएल सूची से हटा दिए गए थे। 12000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वाले परिवारों को इसी महीने से राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन अभिमन्युपुर गांव में खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्या सुन रहे थे। इस दौरान उनके सामने जो जमीनी हकीकत नजर आई उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत उपरोक्त फैसला ले लिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के पास एक सर्वे की रिपोर्ट यह थी कि 9000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की औसत आय 180000 रुपए है, लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि जिन परिवारों का कुल वार्षिक बिजली बिल 12000 रुपए है उनकी औसत आय 180000 रुपए मानी जाएगी। जिन परिवारों का राशन 9000 रुपए से अधिक बिजली बिल होने की वजह से नहीं मिला है उन्हें इसी मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन से बड़े वर्ग को फायदा होगा।

प्रदेश में बढ़ाई जा रही हैं मूलभूत सुविधाएं

मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जिला के गांव धुराला में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हरियाणा में आधारभूत विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सड़क, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है। लोगों को किसी भी योजना के लाभ के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, सभी प्रकार के लाभ ऑनलाइन मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा सब परिवारों का डाटा इकट्ठा किया गया है। 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के स्वत» ही राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुरुक्षेत्र जिला का ही चयन किया गया था। कुरुक्षेत्र जिला में 44 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं।

धुराला में आयुष्मान कार्ड बनाए

गांव धुराला में 2654 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यही नहीं इनमें से 523 लोगों ने इस योजना के तहत फायदा उठाया है और सरकार की ओर से 52 लाख 23 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसकी पेंशन भी खुद ही बन जाएगी। इस गांव में 13 लोगों की पेंशन अपने आप बनी है।

तालाबों की सफाई कराएं सरपंच

मुख्यमंत्री ने करीब 10 सरपंचों को आश्वस्त किया कि तालाबों से संबंधित सफाई के कार्य वह स्वयं करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में लिखित रूप में देना होगा और तालाब की खुदाई का जो भी पैसा होगा, वह उन्हें प्रदान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जब भी गांव में तालाब की खुदाई हो तो उससे निकलने वाली गाध को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करें यह फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है।

प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 31 जुलाई, 2023 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

Haryana-eSamikSha

राज्य सरकार 'हरियाणा-ई-समीक्षा पोर्टल' शुरू करेगी, ताकि प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष अपनी प्रस्तुतियों के दौरान लिए गए निर्णयों पर निगरानी कर सकें।

सहकारी चीनी मिलों में रिकॉर्ड उत्पादन

सहकारी चीनी मिलों का इस बार बेहतर प्रदर्शन रहा है तथा 10.75 प्रतिशत चीनी का उत्पादन करके शाहबाद मिल ने इस साल 7.50 लाख क्विंटल चीनी उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया है। सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल ने राज्य के एकमात्र कुरुक्षेत्र - शाहबाद में चल रहे एथनॉल प्लांट, चीनी मिल, वीटा प्लांट का दौरा कर उत्पादन का अवलोकन किया और चीनी एवं बिजली उत्पादन सहित प्रतिदिन की जा रही क्रेशिंग के बारे में भी जानकारी ली।

चीनी मिल ने किसानों की 80 प्रतिशत गन्ने की लगभग 263 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया है शेष राशि का जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि समय पर किसानों को गन्ने की पेमेंट मिले और चीनी मिलें भी आत्मनिर्भर बनें। शाहबाद प्लांट को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

शाहबाद मिल प्रतिदिन हजारों क्विंटल गन्ने की पिराई कर रही है। इसके अलावा मिल में 60 के एल पी एथेनॉल बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 53 केएलपी एथेनॉल का उत्पादन किया है। एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य अवश्य पूरा किया जायेगा। इस प्लांट के प्रदर्शन के आधार पर ही राज्य की अन्य मिलो में भी एथेनॉल प्लान लगाए जा रहे हैं ताकि मिलो को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

मंत्री ने कुरुक्षेत्र के वीटा मिल्क प्लांट का दौरा किया और अधिकारियों को प्लांट का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। प्लांट में प्रतिदिन 14 हजार लीटर दूध घी की पैकिंग कर वार्षिक 126 करोड़ का कारोबार किया जा रहा है।

घाटे को पूरा करें मिलः बनवारी लाल

सहकारिता मंत्री डॉ.बनवारी लाल ने कहा कि मिल ने 5 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। सरकार मिलों से लगभग 4.10 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है लेकिन 6.10 रुपए बिजली दे रही है। इस प्रकार मिलों को प्रति यूनिट लगभग दो रुपए का नुकसान हो रहा है इस बारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विचार विमर्श किया जाएगा ताकि मिलो के इस घाटे को पूरा किया जा सके।

पशुओं के लिए 200 एंबुलेंस खरीदने का लक्ष्य

हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को विभाग द्वारा 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और आगे एक लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने और पशुपालकों की सुविधा के लिए 200 एंबुलेंस खरीदने का लक्ष्य है।

पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। नये सरकारी पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय खोलने और उनके अपग्रेडेशन कार्य का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुराने सरकारी पशु चिकित्सालयों और पशु औषधालयों की रिपेयर करने का कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। पशुओं को मुंहखुर और गलघोटू बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य 20 मई से शुरू किया जाएगा।

पशुपालकों की सुविधा के लिए राजकीय लाइवस्टॉक फॉर्म को पुनः स्थापित करने और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जायेगा। हरियाणा के छह जिलों में बनी पॉलीक्लिनिकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मॉडर्न मशीनें खरीदने तथा पुरानी बंद पड़ी मशीनों को ठीक करके चालू करने के निर्देश भी हुए हैं। सभी पॉलीक्लिनिकों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भरे जाने हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मंत्री ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे भेड़ और बकरियां पालकों के लिए नई स्कीम बनाएं ताकि बेरोज़गार युवाओं को रोजगार मिल सके।

प्राकृतिक खेती का फायदा ले रहे रेवाड़ी के किसान

संगीता शर्मा

स्वस्थ जीवन के लिए प्राकृतिक खेती बेहतरीन विकल्प है। यह खेती धीरे-धीरे समय की ज़रूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत में अधिक पैदावार हो सकती है। इतना ही नहीं किसानों को इससे अपेक्षाकृत अधिक आमदनी भी होती है।

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को ज़ागरूक और प्रशिक्षित करने के साथ-साथ संसाधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके फ़ायदे और रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देती कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं।

अरावली किसान क्लब का गठन

रेवाड़ी अपने साथ-साथ अभी पूरे एन.

सी.आर के उपभोक्ताओं के लिए ज़हर मुक्त अनाज, दालों, फल, सब्ज़ियों व सरसों तेल का भरोसेमंद हब बनता जा रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर के लोगों का ध्यान रेवाड़ी की तरफ़ आकर्षित होता जा रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए अभी कृषि विभाग रेवाड़ी में बागवानी विभाग के साथ-साथ अन्य खेती-बाड़ी से संबंधित सरकारी संगठनों के सकारात्मक सहयोग से ज़ल्द काफ़ी ऐसे प्रोग्राम जिले में चलाने जा रहा जिससे केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्राकृतिक खेती व मोटा अनाज के स्वप्न को पूरा किया जा सकें।

कृषि विभाग रेवाड़ी ने जिले में 'दा अरावली किसान क्लब' का गठन करके सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी दी है कि पूरे जिले मे कृषि कार्यक्रमों से जिले के एक-एक किसान को जोड़ा जाए व सब का साथ सब का विकास हो सके।

एग्रो इंडस्ट्री से मिलेगा रोज़गार

केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन व बाजरे (मिलेट्स) की सही कीमत को बढ़ावा मिला है। इसी के अनेक उदाहरण कृषि विभाग ने जिले में बनाए हैं जैसे पिछले कुछ वर्षों से खेती व किसानों की झांकी गणतंत्र दिवस व अन्य सामाजिक व प्रशासनिक कार्यक्रमों में देखने को मिलती हैं।

प्रदेश का पहला जिला रेवाड़ी है जिसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने जिले का प्राकृतिक खेती का प्रशसनिक ब्रांड एम्बेसडर 26 जनवरी, 2022 को जिले के युवा प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को बनाया। इसके बाद इस वर्ष आठ किसानों को प्राकृतिक खेती की स्पेशल मास्टर ट्रेनिग दिला करके जिले को प्राकृतिक खेती के आठ मास्टर ट्रेनर दिये है।

किसान कराएं पंजीकरणः एसडीओ दीपक यादव का कहना है कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है, इसके लिए खाद्यान ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती करवाई जाती है।

जैविक उत्पादों की बिक्री बढ़ी

प्रगतिशील किसान यशपाल खोला का कहना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसान अपना पंजीकरण करवाते हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी से दूसरों राज्यों के उपभोक्ताओं के लिए ज़हर मुक्त अनाजों, दालों, फलों, सब्ज़ियों व सरसों के तेल की सप्लाई की जा रही है और ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावाः

मास्टर ट्रेनर नितेश कुमार व नरेंद्र कोसली का कहना है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी व प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए चार बड़े ड्रमों के लिए हर किसान को 3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जैविक खेती के प्रगतिशील किसान दूसरों किसानों के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं।

महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल द्वारा बागवानी क्षेत्र के लिए विभिन्न कोर्स शुरू किए गए हैं। जिनसे युवा न केवल खुद नौकरी पा सकते हैं, अन्य को भी रोज़गार दे सकते हैं।

साइबर अपराध रोकने के लिए सभी 29 साइबर पुलिस थानों में आईटी एक्सपर्ट रखे जाएंगें। पुलिस कर्मियों को संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।

ग्राम पंचायतों को मिले 46 नए खंड विकास अधिकारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के ग्राम सचिव एवं सरपंचों से मिलकर उनके गांव का 'ग्राम पंचायत डिवलेपमेंट प्लान' (जीपीडीपी) तैयार करवाएं और ज़ल्द से ज़ल्द पोर्टल पर अपलोड करवाएं। उन्होंने घोषणा की कि आवश्यतानुसार राज्य में खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के सरकारी आवास बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के नए बैच में चयनित एवं नियुक्त अधिकारियों के साथ परिचय कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से एक-एक करके परिचय किया और उनको ईमानदारी एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। खंड विकास पंचायत अधिकारियों के वर्ष 2023 के बैच में कुल 46 खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों का चयन हुआ है। इनमें एमबीबीएस डॉक्टर से लेकर एमटेक, एमएससी, लॉ डिग्रीधारकों के अलावा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त खंड विकास एव पंचायत अधिकारियों को राज्य सरकार की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि इन्हें पारदर्शी एवं ईमानदारी तरीके से लागू करके अपनी प्रतिभा का परिचय देने की आपकी बारी है। उन्होंने पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से तालमेल करके तटस्थ होकर काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी को इनोवेटिव आइडिया सूझता है तो वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अवश्य शेयर करे ताकि विश्वसनीयता पाए जाने पर पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ग्राम स्तर पर प्राथमिकताओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि गांवों में तालाबों की सफाई, शिवधाम का रखरखाव, पार्क-व्यायामशाला व वेलेनेस सेंटर का निर्माण आदि कार्य करवाए जा रहे हैं, ऐसे में सभी नए नियुक्त खंड विकास पंचायत अधिकारी इन कार्यों में रूचि लेकर काम करें।

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर ने नए खंड विकास पंचायत अधिकारियों को ग्रामीण स्तर के परिवार पहचान पत्र के बकाया रजिस्ट्रेशन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों व ग्राम सचिव से मिलकर स्वामित्व योजना के तहत प्रोपर्टी आईडी के रजिस्ट्रेशन को भी स्पीडअॅप करने के निर्देश दिए।

-संवाद ब्यूरो

स्थानीय उद्योगों की जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए एक व्यापक कौशल विकास योजना बनाने हेतु अतिरिक्त उपायुक्तों के नेतृत्व में जिला स्तरीय एजेंसी का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को विभिन्न उद्योगों में आवश्यक विशिष्ट कौशल और स्थानीय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करना है।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम) और इसकी कार्यान्वयन योजना पर बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्तों ने वर्चुअली रूप से भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विशेष रूप से नूंह जिले में +2 ड्रॉपआउट छात्रों को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करने के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष अभियान चलाने और विद्यार्थियों को उनमें नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए समारोह आयोजित करें।

इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि विदेशों में हरियाणवी युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश सहयोग विभाग, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय एवं युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग में हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल स्थापित किया है। अतिरिक्त उपायुक्तों को समीक्षा बैठकों में जिला परिषद के महापौरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौशल विकास कार्यक्रम स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों के अनुकूल हों। जय भारत मारुति के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। रिलायंस स्वराज इंडस्ट्रीज के सहयोग से मशीनिस्ट प्रशिक्षण और एयरटेल के सहयोग से 5जी प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होगा।

आईटीआई में प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली लागू: हरियाणा कौशल विकास मिशन एक अभिसरण पोर्टल विकसित कर रहा है। यह पोर्टल एचएसडीएम और स्किल इंडिया पोर्टल के एकीकरण को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, शैक्षिक संस्थानों में कौशल प्रमाणन के लिए पुरस्कृत निकाय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद की मान्यता देने के संबंध में संबंधित विभागों को पत्र जारी किए गए हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

एक वर्षीय आई.टी.आई. पाठ्यक्रम में तीन से छह माह तथा दो वर्षीय आई.टी.आई. पाठ्यक्रम में 6 से 12 माह का ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 290 व्यापार इकाइयों के लिए प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) के तहत 62 सरकारी आईटीआई और 189 उद्योगों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और 6835+डीएसटी सीटों की पेशकश की गई और प्रशिक्षुओं को डीएसटी व्यापार इकाइयों में नामांकित किया गया।

जेआईएम-जीआईटीआई की स्थापना: जैक्कार फाउंडेशन, मानसेर के सहयोग से आईटीआई, पानीपत के परिसर में स्थापित एक प्लम्बर लैब स्थापित की जाएगी। सैमसंग इंडस्ट्रीज के सहयोग से आईटीआई, गुरुग्राम परिसर में एक रेफरी और एयर कंडीशनिंग लैब स्थापित की गई है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आईटीआई, गुरुग्राम में एक भू सूचना विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा, मारुति सुजुकी लिमिटेड के सीएसआर फंड से जापान उन्मुख ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऊंचा माजरा में जेआईएम-जीआईटीआई की स्थापना की गई है। वर्तमान में 20 इकाइयों में 432 प्रशिक्षु नामांकित हैं।

'गुरु शिष्य सम्मान योजना'

दिव्यांगों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एचएसडीएम ने ऑब्जर्वेशन होम, अंबाला में रहने वाले बच्चों (कानून के साथ संघर्ष में) को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसने दिव्यांग उम्मीदवारों के कौशल प्रशिक्षण के लिए डीसीएफ क्रिकेट फेडरेशन को भी सूचीबद्ध किया है।

-संवाद ब्यूरो

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए पोर्टल पर भी होगा आवेदन

मुख्यमंत्री ने एचकेआरएनएल एंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया

हरियाणा के युवाओं को रोज़गार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संस्थागत तरीके से निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एचकेआरएनएल एंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया है। अभी तक विभिन्न कंपनियों से आई लगभग 6000 मैनपावर की मांग के अनुरूप आज 12 हज़ार से अधिक युवाओं को कंपनियों में इंटरव्यू के लिए ऑफर भेजा गया है। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े उद्योगपतियों, विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योग काफी समय से इस प्रकार की योजना चाहते थे।

उद्योगपति करा सकते हैं पंजीकरण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल पर उद्योगपति पंजीकरण करा सकते हैं और मैनपावर की मांग भेज सकते हैं। रोजगार योग्य उम्मीदवार भी स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एचकेआरएनएल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित उद्योगों द्वारा मांग की गई मैनपावर के अनुपात के अनुसार उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, एचकेआरएनएल कुशल, अर्ध कुशल व अकुशल मैनपावर के लिए 12,000 से 30,000 रुपये तक विभिन्न वेतन स्लैब में रोजगार प्रदान करने में सक्षम होगा। राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अनुदान योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन अनुदान योजना के तहत ए, बी, सी और डी ब्लॉक में सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े एवं मेगा परियोजनाओं की नई स्थापित इकाइयों को सात साल के लिए कुशल,अर्ध कुशल व अकुशल श्रेणियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। एचकेआरएनएल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उद्योग की मांग के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचकेआरएनएल संबंधित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उद्योग की मांग के अनुसार उपयुक्त कौशल प्रशिक्षण देगा। इसके लिए एचकेआरएनएल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जैसे अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से मैनपावर के लिए प्रशिक्षण व प्रमाणन की व्यवस्था करेगा। कौशल विश्वविद्यालय ने 50 से अधिक कंपनियों के साथ एमओयू किया है।

युवाओं को रोज़गार

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए भी एक नया प्रकल्प शुरू किया है। इस नए पोर्टल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उद्योग अपनी जरूरतों के अनुसार मैनपावर की मांग कर सकेंगे। इस दौरान अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एचकेआरएनएल के पास विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि व कुशल उम्मीदवारों का पंजीकृत डाटा है। यहां से उम्मीदवारों का मूल्यांकन हो सकेगा।

-संवाद ब्यूरो

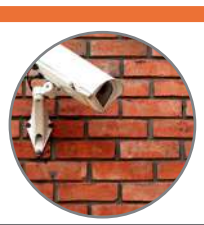

हरियाणा के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य लगभग 75 प्रतिशत हो चुका है, आगामी 15 जून, 2023 इसे पूरा कर लिया जाएगा।

छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है।

सार्वकालिक मार्गदर्शक श्रीमद्भगवद्गीता

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के श्रीमद्भगवद्गीता के सार्वभौमिक ज्ञान को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए किए जा रहे सार्थक प्रयासों के चलते ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। कैनबरा के फेडरल पार्लियामेंट में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में भी 'गीता' की प्रासंगिकता और बढ़ गई है।

हरियाणावासियों के लिए यह गर्व की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की स्वयंसेवी संस्थाओं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया की पावन धरा पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया।

मनोहर लाल ने कहा कि गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाश पुंज है, जो काल, देश और सीमाओं से परे है, जो सर्वकालिक, सार्वभौमिक और चिरस्थायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए सार्थक है। उनके मार्गदर्शन से हरियाणा सरकार गीता के इस ज्ञान को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है।

हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए गया। महोत्सव में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज व पानीपत से विधायक महीपाल ढांडा शामिल हुए।

अहंकार नहीं करना चाहिए:

सीएम ने कहा कि गीता के श्लोक में कहा गया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने यह भी संदेश दिया है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा में निहीत है। गीता का यह संदेश यदि विश्व के सभी लोग समझ लें तो फिर सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सारा संसार एक परिवार हो जाएगा।

सभी समस्याओं का हल श्रीमद्भगवद्गीता में

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की सभी समस्याओं का हल श्रीमद्भगवद्गीता में निहित है। भगवान श्रीकृष्ण की अमरवाणी में गीता में श्रेष्ठ समाज बनाने के उपाय दिये हुए हैं। इसके पाठ और प्रयोग में हम ऐसा समाज बना सकते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आनंदित एवं सुखी हो सकता है। इसके पाठ एवं आचरण से एक साधारण आदमी उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकता है।

स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी गुरू गोरखनाथ की जीवनी

हरियाणा सरकार की संतों व महापुरुषों की राज्य स्तर पर जयंती मनाने की परंपरा की कड़ी में करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरू गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर, रोहतक में गुरू गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ (चेयर) स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी तथा नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी-पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा।

बच्चों को बाबा गोरखनाथ की शिक्षाओं से अवगत करवाने के लिए गुरू गोरखनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्य' म में किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्र वादक, जो एक आयु के बाद वाद्य यंत्रों को बजाने में सक्षम नहीं रहते, उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से पेंशन योजना तैयार कर रही है, जिसका जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा।

योगी समाज जहां सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरू गोरखनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी समाज के लोग अपनी धर्मशालाओं की सूची प्रदान कर दें, जहां भी जो आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि योगी या घुमंतु समाज के जिन परिवारों में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है।

संत-महापुरुषों का अतुलनीय योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की कुरुतियों को दूर करने में संत-महापुरुषों का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, इसलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत-महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने हेतु संत-महापुरुष सम्मान एवं प्रचार-प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संत-महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं।

- संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

बिजली चोरी, पड़ज्या भारी

- रसीले, आज तो रात नैं गाम में बिजली आल्यां का छापा पड़्या था।

- हां भाई सुणा तो मनै भी था, पर न्यू ना बेरा पाट्या अक बिजली किसकै पड़ी?

- बिजली पड़ी लांड्यां कै। रात नै एसी कूलर चलाकै खैं- खैं सोवैं थे।

- आच्छा फेर?

- फेर के रात 12 बजे सी बिजली आळे आ धमके। बिजली का मीटर घर तैं बाहर खंभे प लागर्‌या था। बिजली आल्यां नै पहल्यां मीटर देख्या। देख्या, घर में तो एसी सारके चालरे सैं और मीटर जमा जाम सै।

- आच्छा, यू के चाळा भाई। इतणे पंखें, कूलर व एसी चालरे हों और मीटर बुत बण्या लटकर्‌या हो तो कमाल की बात सै।

- हां छबीले, बिजली आल्यां नै बैटरी मार-मारकै देख्या। कितोड़ कोए इस तार नजर कोन्या आया जिसतैं न्यू बेरा लागज्या अक बिजली की चोरी का खखाट उठर्‌या सै।

- बिजली चोरी होरी थी और बेरा ना पाट्या?

- पाटग्या ना। बिजली आल्यां का काम ए यू हो सै। भींत में एक प्वाइंट इसा पाया जड़ै शक होग्या, अक हो ना हो तार आड़े कै पावैगा। जो डारेक्ट खंबे ताहीं होगा। और धौरै सी जाकै देख्या तो पाग्या। चोरी पकड़ ली गई।

- आच्छा रै, कमाल कर दिया, बिजली आल्यां नैं।

- बिजली आल्यां नै मौके की बीडीओ फिल्म भी बणाई। इतणे में लांडे नींद तैं जाग लिये। बिजली

आल्यां नै बता दिया अक भाई यो बिजली चोरी का केस बणा दिया सै। आपणा भुगत लियो।

-लांड्या धौरै कहण-सुणन नै कोई बात कोन्या थी। क्यूंके मौके पर रंगे हाथां चोरी पकड़ी गई थी।

- भाई उनकै तो कम से कम पचास हजार का चेपवा ला दिया होगा। यानी जो फसल में बचत होई होगी वा मोरी में कै।

- पर भाई छबीले एक बात कोन्या समझ में आती। खट्टर सरकार नै बिजली के रेट इतणे सस्ते कर राखें सैं अक गरीब आदमी भी भर आवै सै तो इन जमींदारां कै के जोर पड़ै सै। असल में आदत खराब होरी सै। पाछली सरकारां में कदे बिजली का बिल नहीं भर्‌या।

- रसीले, इसमें सरकार के करावैगी। जिब लोग खुद नहीं सुधरणा चाहते तो के करया जा सकै सै। बेईमानी खुद करैं सैं और कमी सरकार में काढ़ैंगे।

- छबीले, यो माड़ी बात सै। जिब मुख्यमंत्री खुद ईमानदार सै और ईमानदारी तैं बिजली देवै सै और बिल भरावै सै तो चोरी नहीं करणी चाहिए। थोड़ा थोड़ा बिल आवै सै, इतणे पिस्सां में कोई भार्‌या- हळवी ना होती। भर देणा चाहिए।

- लांड्यां कै चोरी पकड़ी गई। जुर्माना भरा जागा, बेज्जती के झंडे बंधैंगे वे अलग।

- छबीले, सरकार नै उन परिवारों को बीपीएल में मान्या सै जिनकै बिजली का बिल महीने का एक हजार रुपए तक आवै सै। जड़े ताहीं मेरा मानणा सै, इतणा बिल 70 प्रतिशत परिवारां का कोन्या आता। के ये लोग उनतैं भी गए। और जिनकै इसतैं घणा बिल आवै सै तो वे बिजली जलाते होंगे। जलावैं सैं तो बिल भरणा भी चाहिए।

- रसीले, बोहत से लोग ऊं तो बड़े ज्ञानी-ध्यानी कुहाणा चाहवैं सैं, पर नीत में दो आन्ने का सुवाद कोन्या होता। उनके असल करेक्टर में डांगर हांडे पावैं सैं।

- हां भाई जो माणस घर तैं बाहर घणा चौधरी पाकता दिखैगा ना, उसकी घर में कतई कोन्या चालती पावै।

- चलो भाई, हामनै के लेणा, पर मैं तो न्यूं कहणा चाहूं सूं अक जिब ताहीं म्हारा आपणा आपा सही नहीं होगा, तब ताहीं इस देस का भला नहीं हो सकता। यो बात एक बिजली की नहीं हर मामले में लागू हो सै।

- छबीले, थोड़ा रुक। बिजली महकमे आळे, इसे मीटर लाण लागरे सैं अक, फोन की तरियां पहल्यां रिचार्ज कराओ और बिजली खर्च करो।

- आच्छा रै, न्यू होवैगी। जै गंडासे पै न्यार काटते-काटते रिचार्ज खत्म होग्या तो न्यार भी आधम रहज्यागा? न्यार ए नहीं, चोखा सा रिचार्ज ना कराया तो बिलावणी भी धरी की धरी रहज्यागी।

-छबीले, जमाने का कतई पड़गड़ास पाटर्‌या सै। बेरा ना के के देखणा होगा। ले इसै बात पै होक्का भरल्या।

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com